


प्रतिवादीगण के सम्मन मय प्रतियों के प्रस्तुत किये हैं अथवा नहीं।
किंक अरण है तो बैंक पक्षकार है या नहीं।
अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ

श्रीकमल / SDM लाहौर

वकील वादी द्वारा एडमिशन बहस की गई। वकील वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष विवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 विधि विरुद्ध तरीके से गलत जगह पर नक्का बनाकर सिंचाई सुविधा से वंचित कर रहे हैं, अतः धारा 92ए राजस्थान कारतकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादीगण को व्यादेशित किया जावे कि वे पत्थर संख्या 79/64 (48) किलान. 25 के दक्षिण पूर्ण बने हुए नक्के को किसी प्रकार से छेड़छाड़ या हटाने व तोड़ने से बाज व मजबूत रहे।

न्यायालय द्वारा वकील वादी से यह स्पष्टीकरण चाहा गया कि किस प्रकार हस्तगत वाद धारा 92ए के तहत संस्थित किये जाने संबंधी तात्विक आवश्यकताओं का पूरा करना है -

- क्या सिंचाई संकर्म यथा नक्के का निर्माण, स्थान परिवर्तन आदि राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955 द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं? क्योंकि धारा 92ए के तहत कोई वाद केवल राजस्थान अधिधृति अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के ~~विषय~~ प्रवर्तन के लिए ही फाईल किया जा सकता है।
- यदि हां, तो क्या वॉचिंत अनुतोष (व्यादेश) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अध्याय 7 अथवा 8 के अधीन देय हैं?

वकील वादी ने अपनी बहस में दलील प्रस्तुत की कि राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(24) परिभाषा खण्ड में भूमि की परिभाषा में जल को भी शामिल किया गया है। अपनी  के समर्थन में वकील वादी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 'शमचन्द्र vs. लखा, 1972 RRD 118' प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार 'Well constructed for agricultural purposes through not defined in the Act,

included within definition of land.'

न्यायालय द्वारा संबंधित न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अवलोकन किया गया एवं वकील वादी द्वारा वृद्ध में उधार गए हिन्दुओं पर मनन किया गया।

न्यायालय के मुख्य प्रेषण एवं निष्कर्ष निम्नानुसार हैं-

- (i)- धारा 5(24) के अन्तर्गत भूमि में जल शामिल नहीं है, वरन् जल से ढकी हुई भूमि; भूमि के अन्तर्गत शामिल है। नक्का, मोटा आदि सिंचाई संकर्मों से संबंध सूचनाएँ हैं।
- (ii) सिंचाई संकर्मों से संबंध अधिकार राजस्थान कारतकारी अधिनियम द्वारा प्रदत्त नहीं है बल्कि राजस्थान सिंचाई तथा जल निकास अधिनियम, 1954 के तहत प्रवृत्त होते हैं। अतः न्यायालय की राय में वादी द्वारा वांछित अनुतोष को धारा 92 स. रा. का. अ. के तहत प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता।
- (iii) हस्तगत वादपत्र में न तो वादी के पक्ष में विद्यमान किसी बाधभता के संग का निवारण का बिन्दु है, न कोई वे बाधयता है, जो संविदा से उद्भूत होती हो और न ही वादी के सम्पत्ति के अधिकार के उपरोक्त पर आक्रमण किया जाता अन्तर्वलित है। फलतः हस्तगत वादपत्र में वांछित अनुतोष विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अध्याय 7 अथवा 8 के तहत नो देय नहीं हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार वादी द्वारा हस्तगत वादपत्र में वांछित अनुतोष (अधिकार) राजस्थान कारतकारी अधिनियम द्वारा प्रदत्त योग्य न होने के कारण एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अध्याय 7 अथवा 8 के तहत न आने के कारण हस्तगत वादपत्र सडमिशन स्टेज पर हो खारिज योग्य है।

—: आदेश :-

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 15। सीपीसी के तहत रतदू द्वारा खारिज किया जाता है।

फैसला सरे इजलास सुनाया गया।

14/9/21
पिपल कुमार
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़